कारकार्य वर्णनी प्रकेश को र कार्यों पर निकार चेन्द्रीके विकार निकार



डी०एस० गर्ब्याल, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक. शहरी विकास निदेशालय. उत्तराखण्ड, देहराद्न।

शहरी विकास अनुमाग—2 देहरादून : दिनांक ² फरवरी, 2016

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगर पंचायत, नौगांव को अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि नगर पंचायत, नौगांव द्वारा निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के आगणन, अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराए गए हैं। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, नौगांव द्वारा निकाय क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु कार्यवार कुल ₹10.68 लाख (रूपये दस लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि
1-	एन०एच० रोड से मुगरा पानी धारा तक जाने वाले मार्ग का सी०सी० निर्माण।	2.00
2-	पानी धारा से सरस्वती इंटर कॉलेज तक जाने वाले मार्ग का सी०सी० निर्माण।	2.00
3-	मुराडी में एन०एच० से अजय रमोला एवं गणेश भवन तक सुरक्षा दीवार एवं सी०सी० सड़क निर्माण।	1.90
4-	एन०एच० से प्रताप सिंह के भवन तक जाने वाले मार्ग का सी०सी० निर्माण।	2.00
5—	देहली यमुनोत्री मोटर मार्ग से नौगांव की ओर श्री नवीन के घर तक नाली एवं पी0सी0 खडिंजा निर्माण।	2.78
	योग-	10.68

उपरोक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है :--

उंक्त धनराशि कुल ₹10.68 लाख (रूपये दस लाख अडसठ हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, नौगांव (उत्तरकाशी) को बैंक डाफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी

भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुरितका, बजट मैन्अल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति Ш. नियमावली, 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते

समय का कडाई से पालन किया जाए।

v. सभी निर्माण कार्य समय—समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

VI. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी

पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VII. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

VIII. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं योजनाओं / कार्यों पर किया जायेगा, जिस हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

IX. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा

उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

x. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

XI. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमित अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XII. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराए जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक

स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

XIII. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रंखी जायेगी।

v. धनराशि का दिनांक 31-3-2016 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का

विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015—16 के आय—व्ययक के **अनुदान** सं0—13 के लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत— 191—स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"—'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

संलग्नक-अलॉटमेन्ट आई डी-s.1.4.0.3.13.0.0.3.2.

भवदीय, / (डी0एस0 गर्ब्याल) सचिव।

सं0-384 (1)/IV(2)-शा0वि0-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) / महालेखाकार (आर्डिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2. निजी सचिव, मां० मुख्यमंत्री जी / शहरी विकास मंत्री जी।
- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23—लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

7.

,वित्त अनुभाग—2./संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन। निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, नौगांव। बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून। 10.

11.

आज्ञा से, (डी०एम०एस० राणा) उप सचिव।